B.A. Part 2

Paper IVth

19.10.20

बारहवें वित्त आयोग के मुद्दे और चिन्ताएं —

(Issues and concerns)

- बारहवें वित्त आयोग ने संघीय व्यवस्था को कई ~~कुछ~~ मुद्दों और समस्याओं से पीड़ित पाया। उनमें से कुछ अति जटिल थे और उचित संस्थानिक सुधारों और राजनीतिक दृढ़ता के अभाव में उनके समाधान की संभावनाएँ भी शून्यतुल्य थीं।
- केन्द्र से राज्यों को साधन अंतरण की व्यवस्था और संघीय व्यवस्था की त्रुटियाँ एक दूसरे को बढ़ावा दे रही थीं।
- आयोग की विचारणीय सामग्री में इसे केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय वित्त व्यवस्था के पुनर्गठन की एक योजना तैयार करने का आदेश दिया गया था, ताकि इसे अविराम घाटों से छुटकारा मिल सके और ~~दीर्घ~~ दीर्घावधिक वित्तीय वहनीयता प्राप्त हो सके। इस चिंतापूर्ण स्थिति के कई कारण थे। -
- कई राज्य और लगभग सभी स्थानीय निकाय अपने राजस्व स्त्रोतों का इष्टतम दोहन करने से कतराते थे।
- राज्यों की केन्द्र के प्रति ऋणदेयता बढ़ती जा रही थी।
- आयोग के समक्ष एक समस्या यह भी थी कि सेवा कर के विभाजन और मूल्यवर्धन कर के पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई थी।
- आयोग के सामने ~~अंतर्राज्यीय~~ अंतर्राज्यीय विषमताओं को कम करने में सहायता देने, और राजकोषीय निष्पादन और न्यायसंगत आवंटन के विरोधाभासों को दूर करने की कठिन समस्याएँ भी थीं।
- इन सब के अतिरिक्त आयोग के लिए कुछ अन्य कठिन निर्णय लेना भी अनिवार्य थे, जैसे कि -

★ केन्द्र से राज्यों को साधन अंतरण का आकार तय करना;
★ सकल साधन-अंतरण में कर-विभाजन और अनुदानों के घटक तय करना;
★ शर्तयुक्त अनुदानों की सिफ़ारिश करना अथवा न करना;
★ स्थानीय निकायों के राजकोषीय ~~स्वास्थ्य~~ ~~स्वास्थ्य~~ स्वास्थ्य के सुधार हेतु प्रभावी उपाए ढूँढ़ना;
★ प्रकोप राहत की व्यवस्था में सुधार हेतु उपाए ढूँढ़ना;
★ राज्यों को ऋण राहत देना; तथा
★ प्रभावी अनुवीक्षण (monitoring) की योजना तैयार करना।

Scanned by CamScanner